5

बेहतर आजीविका की ओर

"(क) व्यापक कृषि, (ख) अति लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों, (ग) विपणन सहित ग्रामीण सेवाओं और (घ) उत्पादन और सहायक सेवाओं हेतु आधारभूत सुविधाओं के लिए ऋण और कार्यक्रमों को जोड़ना (समेकन है)."

—क्राफिकार्ड



- .1 आजीविका संबंधी विशेष प्रयास
- 5.2 अन्य प्रमुख पहलें
- 5.3 वित्तीय समावेशन
- 5.4 बेहतर आजीविकाओं के लिए वित्तीय समावेशन

महामारी के दौरान लॉकडाउन जैसे अल्पकालिक झटकों के बावजूद, भारत ने भूख और गरीबी को समग्र रूप से हटाने की दिशा में दीर्घावधि में अच्छा प्रदर्शन किया है. यद्यपि, इस तथ्य को पूरे देश में समान रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लगभग 65% आबादी मुख्य रूप से मौसमी कृषि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और शहरों में निम्न-कौशल वाली नौकरियों पर निर्भर है. ग्रामीण आबादी की पोषण और अन्य जरूरतों तथा ग्रामीण युवाओं (15-29 वर्ष की आयु), अनुमानत: 25 करोड़ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 'बेहतर आजीविका' ही हमारा सही लक्ष्य है. इस बड़ी आबादी को सीखने, आय अर्जन करने और जिस समुदाय में वे रहते हैं (सामाजिक-आर्थिक रूप से) उसका अभिन्न अंग बनने के लिए एक उचित अवसर की जरूरत है.

नाबार्ड द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम, स्थायी संधारणीय आजीविका और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हैं जिन्हें संरचनात्मक रूप से कृषि से संबन्धित सूक्ष्म-उद्योगों और ग्रामीण उद्यमिता सेवाओं की ओर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ये पहलें ग्रामीण अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों की रोजगार क्षमता में सुधार करते हुए स्व-रोजगार को भी प्रोत्साहित करती हैं. प्रत्येक आजीविका कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य सामुदायिक विकास करना है. कॉपोरेट संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और

सरकारें अनेक ग्रामीण कौशल और आजीविका गतिविधियों के लिए निधि उपलब्ध करवाती हैं.

यद्यपि वित्तीय साक्षरता और समावेशन के बिना इन पहलों से लाभ प्राप्त करना प्राय: अल्पकालिक होता है. सरकारी योजनाओं के लाभों को जानना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए तैयारी सुनिश्चित करना और व्यक्ति के किरयर और उद्यमशीलता के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऋण का लाभ प्राप्त करना ग्रामीण भारत के लिए महत्वपूर्ण है. नाबार्ड की विभिन्न व्यावहारिक पहलों में महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मदद करने की क्षमता है.

5.1 आजीविका संबंधी विशेष प्रयास

आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) और सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) के माध्यम से नाबार्ड ग्रामीण भारत की महिलाओं (परिपक्व स्वयं सहायता समूहों में) और युवाओं को संधारणीय आजीविका हेतु कुशल बनाने पर जोर दे रहा है.



5.1.1 आजीविका के लिए शुरू से अंत तक समाधान

एलईडीपी के तहत संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए कौशल निर्माण के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाया जाता है. बकरी पालन के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण (शोकेस 5.1) और 'माई पैड, माई राइट' कार्यक्रम से मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार जैसे

महत्वपूर्ण अंतर्निहित लक्ष्य भी प्राप्त किए जा रहे हैं (शोकेस 5.2). वित्तीय वर्ष 2022 में 357 एलईडीपी के आयोजन पर ₹1,380.5 लाख का व्यय किया गया जिससे 46,823 सदस्यों के कौशल उन्नयन करने और बैंक ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता की गई और उनके लिए संधारणीय आजीविका का सृजन किया गया.

शोकेस 5.1: आजीविका के साधन के रूप में बकरी पालन

एलईडीपी: गुजरात के धनपुर ब्लॉक में अत्यंत गरीब ग्रामीण परिवारों द्वारा बकरी पालन

उद्देश्य: अत्यंत गरीबी से पीड़ित एवं निम्न-कौशल वाली ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- सभी 95 लाभार्थियों ने सावधि ऋण लिया और समय पर चुका दिया.
- लाभार्थियों की औसत मासिक आय ₹2,000 से बढ़कर ₹4,000 हो गई.
- इस कार्यक्रम से महिलाओं का सशक्तीकरण और उनके आत्मविश्वास में सुधार हुआ और उनकी हिम्मत बढ़ी.

भविष्य की राह ...

- अपने पशुधन को आपातकालीन निधि समझने के बजाय उन्हें एक व्यावसायिक अवसर के रूप में मानने के लिए उनके ज्ञान और व्यवहार में परिवर्तन
- बकरी पालन से संबन्धित सुनियोजित व्यवसाय योजना, जिसका लाभार्थियों के लिए अभाव था.
- बकरी के दूध के विपणन और प्रसंस्करण के लिए अवसरों की तलाश.
- बकरे के मांस की उच्च मांग का दोहन करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य श्रृंखला, अथवा बड़े मांस बाजारों के साथ विपणन संयोजन का विकास.





नोट: एलईडीपी = आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम.

स्रोत: नाबार्ड के गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय के एक अध्ययन के निष्कर्ष.

शोकेस 5.2: मेरा पैड, मेरा अधिकार

एलईडीपी: 3,000 से अधिक गांवों की 14,700 से अधिक ग्रामीण महिला एसएचजी सदस्यों को सैनिटरी नैपिकन के उत्पादन और विपणन के लिए कौशल प्रदान

उद्देश्य: संधारणीय आजीविका अवसर उपलब्ध करवाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों मे मासिक धर्म स्वच्छता की पहुंच में सुधार करना

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

चरण I (फरवरी 2022 तक)



- मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व के विषय में जागरूकता पैदा की गई.
- प्रतिभागियों में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने और संचालित करने के लिए आत्मविश्वास पैदा किया गया.
- आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्तिगत सदस्य और स्वयं सहायता समूह.
- प्रतिभागियों को उनके समुदाय में अधिक सम्मान मिला और उनकी हिम्मत बढ़ी.

भविष्य की राह...

- दूसरे चरण में परियोजना का विस्तार 70 आकांक्षी और अन्य चयनित जिलों में किया जाएगा.
- मैनुअल उपकरण को अर्द्ध-स्वचालित (सेमी-ऑटोमैटिक) उपकरणों में अपग्रेड किया जाएगा.

नोट

- 1. एलईडीपी = आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम; एसएचजी = स्वयं सहायता समृह.
- प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति के बारे में अधिक जानने के लिए https://www.nabfoundation.in/my-pad-my-right-latest-update.html देखें.

स्रोत: नाबार्ड की सहायक संस्था नैबफाउंडेशन द्वारा प्रभाव अध्ययन, जिसने इस संबंध में एलईडीपी की शुरुआत की.

5.1.2 सूक्ष्म उद्यम विकास के लिए कौशल निर्माण

ग्रामीण बाजारों,व्यवसाय की गतिशीलता और उद्यम प्रबंधन की समझ से ग्रामीण आजीविका के लिए सूक्ष्म उद्यमों की संधारणीयता को बनाए रखने को प्रोत्साहन मिल सकता है. वित्तीय वर्ष 2022 में 769 एमईडीपी के माध्यम से 25,745 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों की इन क्षमताओं का

उन्नयन किया गया. जैसा कि वर्ष 2020 में तमिलनाडु के पांच जिलों के प्रभाव आकलन अध्ययन से पता चला है कि उन्होंने सदस्यों को नए क्षेत्रों में कार्य करने और उनकी आय बढ़ाने में मदद की (शोकेस 5.3).





शोकेस 5.3: तमिलनाडु में एमईडीपी के प्रभाव का आकलन

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- 65% प्रतिभागियों ने आय में वृद्धि की जानकारी दी.
- मासिक आय में 196% की औसत वृद्धि दर्ज की गई (इनमें सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाले ब्यूटीशियन थे, इसके बाद प्लेट, झाड़ू, और ऐसी अन्य उपयोगी वस्तुओं के निर्माता और डेयरी विकास से संबन्धित किसान थे).
- 65% ने एमईडीपी प्रशिक्षण के ट्रेड को जारी रखा; 2 साल के बाद 48% (सबसे अधिक प्रतिधारिता दुधारू पशुपालन, मूल्य वर्धित कृषि उत्पाद, सौंदर्य चिकित्सा, कृत्रिम आभूषण, सिलाई, कढ़ाई, आदि में थी).
- 31% प्रशिक्षुओं ने एसएचजी या जेएलजी के माध्यम से बैंक ऋण लिया.
- प्रति प्रशिक्ष् ₹18,000 का औसत बैंक ऋण लिया गया.
- भविष्य के एमईडीपी की संख्या और ट्रेड का निर्धारण एमईडीपी के परिणामों से तय होता है.

नोट: जेएलजी = संयुक्त देयता समृह; एमईडीपी = सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम; एसएचजी = स्वयं सहायता समृह स्रोत: तमिलनाड़ के पांच जिलों में प्रभाव अध्ययन (2020).

5.1.3 महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए कौशल और लिंकेज

विपणन योग्य उत्पादक गतिविधियों को सक्षम बनाने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है और इन गतिविधियों को उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए बाजार, ज्ञान और क्रेडिट लिंकेज की आवश्यकता होतो है. स्व-रोजगार पर आधारित सूक्षम-उद्यमों और कुछ सहकर्मियों के समूहों को ऐसे ज्ञान साझेदारों की आवश्यकता होती है जो 'कैसे करें', 'क्या करें' और 'क्या न करें' की जानकारी दे सकें. नाबार्ड समर्थित पुरानी और नई परियोजनाएं न केवल पारिवारिक आय में वृद्धि करने में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं बल्कि महिलाओं को सशक्त भी बना रही हैं.

उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार

अर्थइम्पैक्ट वेलफेयर फाउंडेशन की ₹5.4 करोड़ की परियोजना का उद्देश्य लखनऊ, रायबरेली और अयोध्या जिलों में नाबार्ड से ₹35 लाख की सहायता से 500 महिला उद्यमियों का संवर्धन करना है (तालिका 5.1) 2

तालिका 5.1: प्रदत्त कौशल और संबद्ध ज्ञान साझेदार

ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल	सम्बद्ध ज्ञान साझीदार
बुनाई (चिकनकारी)	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद
पार्लर/ सैलून में ब्यूटी थेरेपी	अर्बन कंपनी और वीएलसीसी
फ़ूड कार्ट संचालन	फी फूड और स्विगी
वित्तीय समावेशन सखी	माइक्रोसेव कंसिल्टंग
ई-रिक्शा चलाना	आजाद फाउंडेशन

महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता विकसित करना

फ्रेंड्स ऑफ विमेन वर्ल्ड बैंकिंग,इंडिया नाबार्ड से प्राप्त ₹65.4 लाख के सहयोग से गुजरात, नागालैंड और मणिपुर के 19 जिलों में 800 सूक्ष्म उद्योग (400 को क्रेडिट लिंक्ड किया जाएगा) स्थापित करेगा. उसभी महिला उद्यमियों का बचत खातों और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से वित्तीय समावेशन किया जाएगा (इनमें से 50% प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना [पीएमजेजेबीवाई] से भी जुड़ी हैं). इस परियोजना से परिवार की आय में 25% वृद्धि होने की उम्मीद है.

लद्दाख के लूम

लद्दाख लूम महिला सहकारी समिति के माध्यम से खानाबदोश, देहाती, आदिवासी लद्दाखी महिलाओं को कौशल प्रदान करने के साथ ही साथ पश्मीना तथा ऊन की व्यापक मूल्य शृंखला को मजबूत किया जा रहा है. नैबफाउंडेशन की दो वर्षीय परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम और सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण शुरू हो चुका है. इस परियोजना के लिए ₹107.5 लाख (₹13.1 लाख जारी किए जा चुके हैं) का अनुदान स्वीकृत किया गया है.

लाख की खेती के लिए सेमियालता वृक्षारोपण

वित्तीय वर्ष 2022 में नाबार्ड ने झारखंड में अपने जनजाति विकास निधि (टीडीएफ़) के तहत लाख (रेजिन) कीट की खेती के लिए आधा एकड़ भूमि पर सेमियालता वृक्षारोपण करने के लिए दो परियोजनाओं को मान्यता दी. इनका उद्देश्य 1,000 आदिवासी परिवारों को प्रत्यक्ष आजीविका और भूमिहीन लोगों के लिए सहायक गतिविधियाँ प्रदान करना था. अन्य वाडियों से भिन्न लाख कीट की खेती वन-आधारित संधारणीय आजीविका को प्रोत्साहित करेगी जिससे आदिवासी आबादी के पारंपरिक कौशल का भी

लाभ उठाया जा सकेगा. यह परियोजना (4-5 वर्ष के जीवनचक्र के साथ) लाख की मूल्य श्रृंखला में सुधार करेगी, लाख प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करेगी, और निर्यात सहित बाजार को मजबूत करेगी; इस प्रक्रिया में असंगठित और शोषक बिचौलियों पर लाख किसानों की निर्भरता को भी कम किया जाएगा. प्रारंभिक सहायता में वृक्षारोपण, आकस्मिक व्यय और दो वर्षों के लिए आवर्ती लागत शामिल है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम (आईआईएनआरजी), रांची के तकनीकी मार्गदर्शन के साथ 5 वर्ष के लिए हैंड-होल्डिंग सहयोग के लिए 3 वर्ष की अनुदान सहायता दी गई है. यह परियोजना टाटा ट्रस्ट के इनिशिएटिव कलेक्टिव फॉर ईंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव (सीआईएनआई), जमशेदपुर द्वारा संचालित है.

संधारणीय आजीविका हेत् केला फाइबर

केले की फसल फल के अलावा तने (स्यूडो-स्टेम), पत्तियों आदि के रूप में भारी मात्रा में बायोमास भी पैदा करती है. भारत में केले के केवल 10% तने (स्यूडो-स्टेम)का ही उपयोग फाइबर बनाने के लिए किया जाता है और बड़ी मात्रा में बचे तनों को फेंक या जला दिया जाता है जिससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है.

बड़ौदा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा ने फरवरी 2022 में नाबार्ड से प्राप्त अनुदान सहायता से 'वस्त्र निर्माण के लिए केले के तने के उपयोग' पर एक अध्ययन पूरा किया था. अध्ययन के हिस्से के रूप में 18 महिलाओं को केले के तने के फाइबर को निकालने, नरम करने और इसकी महीन धागे में कताई करने (टेक्सटाइल ग्रेड फेब्रिक में बुनाई के लिए) के लिए प्रशिक्षित किया गया था. एक मोटर चालित फीनिक्स चरखे पर दो से तीन प्रशिक्ष एक दिन में औसतन 30 ग्राम केले का धागा निकाल सकते हैं. 4



5.2 अन्य महत्वपूर्ण पहलें

एलईडीपी और एमईडीपी के तहत संधारणीय आजीविका और कौशल के लिए किए जाने वाले प्रत्यक्ष कार्य से इतर ग्रामीण क्षेत्र को गहन सिक्रयता, ज्ञान सृजन और लिंकेज साझेदारों की आवश्यकता है. इनमें से एक प्रमुख घटक कॉरपोरेट संस्थाओं की व्यापक भागीदारी है, जिनके पास कौशल विकास के लिए बेहतर प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं हैं. इसके अतिरिक्त और अधिक स्थान विशिष्ट पायलट परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो सके. नाबार्ड ने इन कार्यों को आगे बढ़ाने के साथसाथ ग्रामीण क्षेत्र के लिए और अधिक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करने हेतु गहन प्रयास किए हैं.

नाबार्ड का टीडीएफ संधारणीय और सहभागी आजीविका कार्यक्रमों यथा पेड़ /बागान आधारित कृषि प्रणाली (वाडी), मिश्रित वाडी (मिश्रित खेती/ बहु-स्तरीय खेती, सटीक खेती, नैट्यूको खेती, आदि); पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ जैसे लघु वन उपज का संग्रहण, हर्बल दवाइयाँ, गोंद, प्राकृतिक रंग, भेड़ पालन, आदि; तथा आदिवासी कला एवं शिल्प और अन्य गैर-कृषि आधारित गतिविधियों पर आधारित आजीविकाओं को सहायता प्रदान करता है. (चित्र 5.1.)

चित्र 5.1: जनजाति विकास निधि (टीडीएफ़) के तहत गैर-वाडी परियोजनाएं

3,530 भूमिहीन आदिवासी परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिए 10 गैर-वाडी परियोजनाएँ







5.2.1 ग्रामीण व्यावसायिक विचारों का उद्भवन करना

ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न व्यावसायिक विचारों को सहायता प्रदान करने के लिए, ₹63.3 करोड़ की सहायता से सात ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर (आरबीआईसी) स्वीकृत किए गए हैं. प्रत्येक आरबीआईसी अलग-अलग चरणों में हैं. 31 मार्च 2022 तक इन इन्क्यूबेशन केंद्रों ने 697 इन्क्यूबेटरों और 225 स्टार्ट-अप्स को सहायता उपलब्ध करवाई है. इन केंद्रों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 लाख किसानों और युवाओं को लाभ हुआ है. केन्द्रों ने वित्त पोषण सहायता के लिए 150 निवेशकों को इनक्यूबेटरों के साथ जोड़ने में भी मदद की है.

5.2.2 हथकरघा से आत्मनिर्भरता

नाबार्ड हथकरघा को सदैव सहयोग करता रहा है क्योंकि हथकरघा का पुनरुद्धार न केवल कारीगरों के लिए बल्कि छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों के लिए गैर-कृषि उत्पादक संगठनों (ओएफपीओ) के माध्यम से सामूहिक रूप से अपनी आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है. हथकरघा पखवाड़े के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों (विपणन गतिविधियों) में ₹60 लाख की बिक्री दर्ज की गई. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मिजोरम, तेलंगाणा और ओडिशा के ओएफपीओ द्वारा 'हथकरघा से आत्मिनर्भरता' थीम पर अनुभव साझा कार्यक्रम; एक फिल्म स्क्रीनिंग; प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चर्चा; और इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे भागीदारों का अभिनंदन करके राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह सफलतापूर्वक मनाया गया. इस अवसर पर भारत में हथकरघा की स्थित पर एक विशेष रुरल पल्स अंक का विमोचन भी किया गया.

5.2.3 स्थान-विशिष्ट परियोजनाएं

पिछड़े क्षेत्रों में आजीविका उपलब्ध करवाने में विविधता से परिपूर्ण गैर-कृषि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने 'मेरा जिला, मेरी परियोजना' के तहत 8 राज्यों में 15 स्थान-विशिष्ट परियोजनाओं हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 में ₹361 लाख मंजूर (₹67.3 लाख संवितरित) किए हैं. परियोजनाओं का उद्देश्य समग्र और वित्तीय रूप से संधारणीय आजीविका समाधानों के माध्यम से लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाना है. इनमें इनपुट आपूर्ति, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानकीकरण, प्रमाणन, गुणवत्ता नियंत्रण, ऋण, पर्यावरणीय मामले, बाजार सहयोग आदि शामिल हैं. अपेक्षित परिणामों में ग्रामीण पर्यटन, हथकरघा, आदि में व्यवहार्य गैर-कृषि उद्यमों का सृजन; संधारणीय रोजगार; उत्पादकता में बढ़ोतरी; ऋण का बेहतर प्रवाह और पहुंच; और जेंडर समानता शामिल है. ये पायलट आधारित गतिविधियाँ भविष्य मे विस्तार की संभावनाओं के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मोड में आरंभ की जा रही हैं.

5.2.4 टाटा स्ट्राइव के साथ दीर्घकालिक जुड़ाव

विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि जब कॉरपोरेट घरानों द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो बेहतर संकाय सदस्यों, संसाधनों, प्रक्रियाओं, स्टाफ, प्रतिबद्ध रोजगार आदि के कारण कार्यक्रम की गुणवत्ता और रोजगार की दर अधिक होती है. इस संदर्भ में नाबार्ड कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ मिलकर अपने कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है. नाबार्ड ने पहली बार टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव्स ट्रस्ट (टीसीआईटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो टाटा ट्रस्ट की कौशल विकास पहल - टाटा स्ट्राइव की कार्यान्वयनकर्ता इकाई है. इस पहल के तहत नाबार्ड अगले 3-5 वर्षों में पूरे भारत में 5,000 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए आजीविका कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. इन कौशल विकास कार्यक्रमों में एंड्रॉइड ऐप डेवलपर, औद्योगिक इलेक्ट्रीशियन, घरेलू इलेक्ट्रीशियन, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, आतिथ्य, सौर तकनीशियन आदि जैसे तकनीकी ट्रेड शामिल होंगे.

5.3 वित्तीय समावेशन

प्रौद्योगिकी और वित्तीय प्रणालियों में ज्ञान के अभाव के कारण, प्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से एक कदम पीछे है, जिसके परिणामस्वरूप प्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास धीमा होता है. वित्तीय समावेशन के बिना कौशल और आजीविका सृजन की पहल भी अधूरी है. वित्तीय समावेशन एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है और इससे समावेशी विकास होता है. प्रामीण आबादी को न केवल अपने वित्तीय अधिकारों, देय राशियों और अवसरों को जानने की जरूरत है, बल्कि अनौपचारिक उधार के जाल से भी बचना चाहिए, जिसने उन्हें पीढ़ियों से गरीब बनाए रखा है. बैंकों में वित्तीय समावेशन की आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए नाबार्ड सहायता उपलब्ध करवाता है जिससे वित्तीय लेनदेन करने में गित आती है. यह डिजिटल और भुगतान स्वीकार आधारभूत संरचना का निर्माण करने के साथ ही साथ डिजिटल एवं वित्तीय जागरूकता गितिविधियाँ भी संचालित करता है.

यद्यपि गरीबी उन्मूलन में सूक्ष्म वित्त की भूमिका पर व्यापक अनुसंधान कार्य हुआ है. तथापि सरकार द्वारा संवर्धित लघु वित्त कार्यक्रमों जैसे स्त्री निधि, डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से दिये जाने वाले सूक्ष्म वित्त के प्रभाव और इसके बिजनेस मॉडल के विशेष संदर्भ में, अब तक अध्ययन नहीं किया गया है. अतः नाबार्ड ने सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंसिअल इंक्लुशन (सीईडीएफआई), नेशनल इंस्टिट्युट ऑफ रूरल डेवलेपमेंट एण्ड पंचायती राज, और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को स्त्री निधि के बिजनेस मॉडल पर अनुसंधान अध्ययन करने का कार्य सौंपा है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा में स्त्री निधि के 603 एसएचजी उधारकर्ताओं के प्राथमिक आंकड़ों के अध्ययन से यह पाया गया कि एसएचजी सदस्यों की 'वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता' और उनकी आय एवं संपत्ति मे सीधा संबंध है. इस संबंध से यह पता चलता है कि वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता एक दूसरे को सुदृढ़ करती है तथा एसएचजी परिवारों की आय में वृद्धि कर उनकी संपत्ति को बढ़ाती है. ऋण और आय के बीच भी सकारात्मक और सीधा संबंध है जो यह इंगित करता है कि यदि एसएचजी परिवारों को नियमित अंतराल पर ऋण स्वीकृत किए जाते हैं तो उनकी आय में वृद्धि होगी.

5.3.1 डिजिटल सक्षमता हेतु सहयोग

वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) योजनाओं का उद्देश्य बैंकों के लिए डिजिटल आधारभूत संरचना की लागत के लिए आर्थिक सहायता देना है. यह ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफ़आई) को अपने डिजिटल टच पॉइंट बढ़ाने के उनके प्रयासों मे सहायता करता है और ग्रामीण ग्राहकों को लाभान्वित करने के लिए उन्हें नवीनतम बैंकिंग तकनीकों और नियामक मानदंडों को अपनाने में सक्षम बनाता है. अधिकांश एफआईएफ योजनाएं अल्पकालिक हैं और (मंजूरी से) एक वर्ष की अविध में लागू की जाती हैं.

5.3.2 वित्तीय साक्षरता और जागरूकता

बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन प्रणालियों और विभिन्न वित्तीय जागरूकता सामग्री जैसे लीफलेट, पैम्फलेट, बैनर आदि के साथ बहुपयोगी मोबाइल वैन तैनात करना हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है (शोकेस 5.4). वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भागीदार के रूप में आरएफ़आई को नाबार्ड के सहयोग के परिणामस्वरूप औपचारिक बैंकिंग के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है.

चित्र 5.2: वित्तीय समावेशन निधि के तहत वर्तमान सहयोग

स्थापित करें	ATM	माइक्रो एटीएम	 एससीबी शाखाएं+एसएफ़बी+स्पेशल फोकस जिलों के स्कूलों और कॉलेजों मे भुगतान बैंक तथा सभी जिलों मे दुग्ध समितियां आरआरबी - स्पेशल फोकस जिलों मे स्कूलों और कॉलेजों + निर्धारित बीसी पॉइंट/ शाखाएं + सभी जिलों मे दुग्ध समितियां आरसीबी + पैक्स + दुग्ध समितियां और अन्य गैर-ऋण समितियाँ
		पीओएस और एमपीओएस डिवाइस	• सभी बैंकों के टियर III-VI केन्द्रों मे
		दोहरा प्रमाणीकरण इंटरफ़ेस	• एसएचजी लेनदेनों के लिए बीसी पॉइंट (एसएफ़बी एवं पीबी और आरआरबी सहित एससीबी)
		भीम आधार पे डिवाइस	• सभी बैंक
		भीम यूपीआई	आरआरबीआरसीबी
ऑन-बोर्ड	•(1)	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	• आरसीबी
	BBPS)) BHARAT BILL PASSENT EYSTEN	भारत बिल भुगतान प्रणाली	आरसीबीआरआरबी
	कंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री	केंद्रीय केवाईसी रजिस्टी	• आरसीबी
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• आरआरबी
समर्थन	₹□□	पॉज़िटिव पेमेंट सिस्टम	• आरसीबी
	ग्रीन पिन के साथ रुपे भुगतान Green PIN	• आरसीबी	
		• आरआरबी	
		एयूए/ केएयू लाइसेन्स	आरसीबीआरआरबी
समर्थन	₹ ₽¥	ग्रीन पिन के साथ रुपे भुगतान सक्रिय करना	आरसीबीआरआरबीआरसीबी

नोट: एयूए = प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी; बीसी = बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट; भीम = भारत इंटरफेस फॉर मनी; केएयू = केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी; केवाईसी = अपने ग्राहक को जाने; एमपीओएस = मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल; पीएसीएस = प्राथमिक कृषि ऋण सिमित; पीबी = निजी बैंक; पीओएस = पॉइंट ऑफ सेल; आरसीबी-ग्रामीण सहकारी बैंक; आरआरबी = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; एससीबी = अनुसूचित वाणिज्य बैंक; एसएफ़बी = लघु वित्त बैंक; एसएफ़डी = विशेष फोकस जिले; एसएचजी = स्वयं सहायता समूह; यूपीआई = यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस





शोकेस 5.4: मोबाइल प्रदर्शन वैन द्वारा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन

उद्देश्य: ईलाकाई देहाती बैंक (ईडीबी) के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन बढ़ाना.

वित्तीय समावेशन पहल: जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और गांदरबल जिलों में वित्तीय साक्षरता शिविरों के लिए छह मोबाइल प्रदर्शन वैन और अभियान सामग्री.

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान ईडीबी ने जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,278 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए जिससे उन्हें व्यापक प्रचार-प्रसार मिला और उनके ग्राहक आधार का विस्तार हुआ.
- द्र-दराज के क्षेत्रों में लोगों ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट खोले हैं.
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ईडीबी (विभिन्न शाखाओं) ने 9,500 से अधिक खाते खोले जिसमें ₹2.3 करोड़ की नई जमाराशि जुटाई गई.
- रुपे कार्ड (सभी ईडीबी खाताधारकों को जारी) से बैंक के लेनदेन की लागत कम हुई और डिजिटल लेनदेन में 60.2% की वृद्धि हुई.
- वित्तीय वर्ष 2022 में नए नामांकन से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अधिक भागीदारी देखी गई:
 - ♦ पीएमजेजेबीवाई : 5,592;
 - पीएमएसबीवाई: 24,184; और
 - एपीवाई : 344.

नोटस:

- 1. एपीवाई = अटल पेंशन योजना; पीएमजेजेबीवाई = प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना; पीएमएसबीवाई = प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना.
- 2. वित्तीय शिक्षा 2020-25 के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति विषय में अधिक जानकारी के लिए देखें https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/1709204627 English%20NSFE%202020-2025-Version%20 Printable.pdf.

5.3.3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन परिपूर्णता

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की सफलता के पश्चात् पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत 117 आकांक्षी जिलों (28 राज्यों) के पीएमजेडीवाई खाताधारकों के नामांकन परिपूर्णता के लिए 10 फरवरी से 31 मई 2022 तक एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया था. नाबार्ड ने नए पीएमजेडीवाई खाता धारकों हेतु बीमा कंपनियों के मौजूदा प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विशेष नामांकन अभियान चलाने के लिए बैंकों और बैंकिंग कोरेंस्पोंडेंट्स के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में ₹6,000 प्रति शिविर का अनुदान दिया. श्रेष्ठ परिणाम के लिए नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों (डीडीएम) ने योजना के उद्देश्य और महत्व के संबंध में बैंकों को जागरूक करने के लिए विशेष जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए. इसके पश्चात् बैंकों ने बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट और वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के साथ मिलकर ब्लॉक और गांव स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता शिविर आयोजित किए.

5.3.4 नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण

नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2017 के लिए उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और आजीविका की हमारी समझ को और बेहतर करने के लिए विस्तारित दायरे और कवरेज के साथ नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2.0 लॉन्च किया जा रहा है. 28 राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों (टियर III से टियर VI केंद्रों) में लगभग 10,000 प्रतिनिधियों द्वारा गांवों / अर्ध-शहरी ब्लॉकों से लगभग 1 लाख परिवारों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया जा रहा है.

5.4 बेहतर आजीविकाओं के लिए वित्तीय समावेशन

नाबार्ड ने अपने वित्तीय साक्षरता, कौशल और आजीविका कार्यक्रमों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ ठोस विचारों पर काम करना शुरू किया है. इनमें से कुछ विचारों से आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत को लाभ मिलने की उम्मीद है:

- भुगतान प्रणाली के टचप्वाइंट की जियो-टैगिंग: भारतीय रिजर्व बैंक के फ्रेमवर्क के आधार पर नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों, सहकारी सिमितियों, व्यापारियों, किसानों और कृषि एवं ग्रामीण विकास (एआरडी) के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य हितधारकों के लिए जियो-टैगिंग की योजना बनाई है. प्राप्त आंकड़ों से क्षेत्रीय समझ पर अंतर्दृष्टि मिल सकेगी, आधारभूत संरचना को बेहतर ढंग से वितरित करने में मदद मिल पाएगी और अतिरिक्त टचपॉइंट की आवश्यकता की पहचान हो पाएगी. इससे फोकस्ड डिजिटल-वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को डिजाइन करने और योजना बनाने में भी मदद मिलेगी. इससे व्यवसायों और बैंकों को डिजिटल भुगतान की मांग से संबन्धित भौगोलिक सूचना प्राप्त हो सकेगी और डिजिटल भुगतान का एकीकरण करने के साथ ही केंद्रीय बैंक की नीतियाँ भी प्रसारित की जा सकेंगी.
- स्कूलों और कॉलेजों में वित्तीय समावेशन शिक्षा: बेहतर आजीविका सृजन के लिए वित्तीय समावेशन एक आवश्यक शर्त है. वित्तीय जागरूकता प्रसारित करने और स्कूलों एवं कॉलेजों के युवाओं में वित्तीय प्रबंधन के विषय में विश्वास पैदा करने के लिए नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) को एंगेज करने की योजना पर विचार किया गया है.
- कौशल और आजीविका: कॉपीरेट साझीदारों की कॉपीरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विंग द्वारा प्राप्त उच्च रोजगार दर के रिकार्ड को देखते हुए नाबार्ड इस प्रकार की और अधिक संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की संभावनाएँ तलाश रहा है. निरंतर प्रयास के माध्यम से ग्रामीण भारत की महिलाओं और युवाओं को आजीविका के व्यापक अवसर प्रदान किए जा सकेंगे.
- ई-श्रम पोर्टल पर नामांकन: ग्रामीण-शहरी पलायन को कम करने के अंतिम उद्देश्य के साथ एलईडीपी और एमईडीपी लाभार्थियों को ई-श्रम पोर्टल पर जोड़ा जाएगा. इससे नाबार्ड को न केवल सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी, बिल्क लाभार्थियों की बेहतर मॉनिटिरंग भी हो सकेगी, एक साथ कई कौशल कार्यक्रमों में उनके नामांकन को भी रोका जा सकेगा और प्रशिक्षुओं द्वारा उद्यम स्थापित करने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी.

नोट

- 1. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (नवंबर, 2019), भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036: जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट. https://nhm.gov.in/New_Updates_2018/ Report_Population_Projection_2019.pdf. 2021 में, लगभग 90 करोड़ भारतीय प्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, जिनमें से 24 करोड़ के करीब 15-29 वर्ष आयु वर्ग में थे (रिपोर्ट की तालिका 6, 9 और 18 के आधार पर अनुमानित; मान्यता 1: अनुमान सटीक हैं; मान्यता 2: ग्रामीण और शहरी आबादी में आयु वितरण समान है)
- 2. यह पहल सूक्ष्म उद्यमियों को औपचारिक ऋण व्यवस्था(बैंकों में बचत खाते) तथा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ती है.
- इसमें चार आकांक्षी जिले और पांच जिले शामिल हैं जहां नाबार्ड की महिला स्वयं सहायता समृह योजना का कार्यान्वयन हो रहा है.
- 4. नाबार्ड (2021), नाबार्ड रिसर्च स्टडी 21, 'कपड़ा बनाने के लिए केले के तने का उपयोग', वस्र और कपड़ा विभाग, परिवार और सामुदायिक विज्ञान संकाय, बड़ौदा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा.
- 5. श्रीपाद ए. दाभोलकर ने अपने कार्य, प्लेंटी फॉर ऑल में, कृषि दर्शन के रूप में पर्यावरण अनुकूल (नैट्यूको) की अवधारणा विकसित की थी जो (i) मृदा (स्वास्थ्य मे सुधार); (ii) जड़ों (विकास और रखरखाव); और (iii) शीर्ष (सूरज की रोशनी लेने) पर जोर देती है; (iv) बाहरी संसाधनों (पानी सिहत) का प्रयोग कम करने पर जोर देती है. भारत सरकार का (अदिनांकित), 'जैविक कृषि प्रणाली पर तकनीकी विवरणिका: राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना', राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. https://midh.gov.in/technology/organic_Management_NHM.pdf.
- 6. 7-22 अगस्त 2021.
- 7. 6 अगस्त 2021.
- 8. नाबार्ड रिसर्च बुलेटिन
- 9. वेतन या स्वरोजगार हासिल करने वाले प्रतिभागियों की संख्या.